

वीजय कुमार और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 3489।

15 सितंबर 1989.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—सर्टिओरारी का रिट—ऐसे का दायरा रिट - ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र पर पहले उठाई गई कोई आपत्ति नहीं ट्रिब्यूनल-पार्टी को उच्च न्यायालय में ऐसी आपत्तियाँ उठाने से रोका गया। माना गया कि त्रुटि को सुधारने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्राधिकार;- ये ऐसे मामले हैं जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना हैं या हैं अधिक मात्रा में या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप। रिट जारी की जा सकती है जहां न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है या जहां प्रक्रिया विवाद से निपटने में अपनाया गया कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। ए ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को रिट में चुनौती नहीं दी जा सकती इस आधार पर कार्यवाही कि प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी को कायम रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त था ढूँढना.

(पैरा 7)

माना गया कि दावेदार ने राष्ट्रपति के समक्ष आपत्ति नहीं उठाई न्यायाधिकरण ने कहा कि कानूनी रूप से उसके द्वारा कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति. यह माना जाएगा कि वे इससे सहमत हैं ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार और आपत्ति रिट में नहीं उठाई जा सकती क्षेत्राधिकार।

(पैरा 8)

इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत प्रार्थना करते हुए याचिका इस मामले के रिकार्ड मंगाते हुए, माननीय न्यायालय निम्नलिखित पर कृपा करेगा:-

(i) निर्णय/आदेश को संशोधित करते हुए एक उचित रिट/आदेश जारी करें (अनुलग्नक पी-8) उस सीमा तक जैसा कि दावा याचिका में प्रार्थना की गई है।

(ii) माननीय न्यायालय द्वारा कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझें; (नमस्कार) कृपया अनुलग्नक पी-1 से पी-8 तक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करें के साथ तिरस्कृत;

(iv) कृपया उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करें के साथ तिरस्कृत;

(v) याचिका की लागत प्रदान की जाए।

## निर्णय

न्यायमूर्तिजी. आर. मजीठिया,

(1) यह निर्णय सिविल रिट याचिका संख्या 3488 से 3492 तक का निपटारा करेगा दावेदार द्वारा दायर 1988 और 2862, 2863, 2865, 2866, और 1989 का 4159-भूस्वामियों, और 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 8084, 8149 और 8172 द्वारा दायर की गई कमल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट.

(2) याचिकाकर्ताओं ने सभी याचिकाओं में फैसले को चुनौती दी है अध्यक्ष, नगर सुधार अधिनियम, 1922 के तहत न्यायाधिकरण, कमल।

(3) मैं 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 3489 में दिए गए तथ्यों का उल्लेख करूंगा। कमल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (संक्षेप में ट्रस्ट), - संकल्प दिनांक के अनुसार 20 अगस्त 1973 को विकास का संकल्प लिया एक योजना (योजना संख्या 37), या 1215 वर्ग मापने वाला क्षेत्र। गज, मेरे संकल्प के अनुसार, धारा 3ओ या तुंजाब एक्सओन इम्प्रूवमेंट एक्ट (या संक्षेप में अधिनियम) के तहत नामांकन, बीपीएसमोअर 7, 197ओ को जारी किया गया था, और 1 जनवरी 197बी को अधिनियम की धारा 42 के तहत घोषणा जारी की गई थी। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि शुरू में प्रांतीय सरकार के स्वामित्व में थी और वर्ष 1804 में एक हॉल सर्वश्री हैती मल बंसी लाल को और दूसरा हॉल नवाब कुतुब दीन और गनुलम भानी खान को बेच दिया गया था। क्रमशः रेली गंज और नवाब गंज के रूप में संबंधित क्षेत्र। इसमें आयताकार आकार के दरवाजे थे, बाड़ों में दुकानें थीं और। रोनी पुरानी दुकानों में, आंगन होते थे जिनका उपयोग मुख्य रूप से किरायेदारों द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपने अनाज, सब्जियों को अलग-अलग ढेर में ढेर करने के लिए किया जाता था। दूसरी ओर दुकानों के प्रांगण मालिकों की निजी संपत्ति थे। 1920 में, नगरपालिका समिति, कमल, (या संक्षेप में समिति) ने बाड़े से होकर गुजरने वाली एक पक्की सड़क का निर्माण किया। समिति ने उस भूमि पर स्वामित्व का दावा किया जिस पर पक्की सड़क का निर्माण किया गया था और इसके कारण समिति और मालिकों के बीच नागरिक मुकदमेबाजी शुरू हो गई। जिला न्यायाधीश, करनाल ने कहा कि दुकानों के आयरनट का क्षेत्र मालिकों की निजी संपत्ति थी और समिति इस पर दावा नहीं कर सकती थी। लाहौर के मुख्य न्यायालय में अपील करने पर, जिला न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया गया,

और इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि दुकानों के सामने का क्षेत्र समिति की संपत्ति थी। मालिकों ने आई.आहोर के मुख्य न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की और प्रिवी काउंसिल ने नवाब बहादुर मुहम्मद रुस्तम अल्ट खान और एक अन्य बनाम कद्रनाल की नगरपालिका समिति (1) में अपने फैसले में कहा कि जिस ज़मीन पर पक्की सड़क का निर्माण किया गया था वह मालिकों की निजी संपत्ति थी। इसने पुष्टि की कि दुकानों के सामने का क्षेत्र मालिकों की संपत्ति थी। मुख्य न्यायालय का निर्णय पलट दिया गया और जिला न्यायाधीश का निर्णय बहाल कर दिया गया।

(4) विजय कुमार और सुरिंदर कुमार याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पल्ली मल और बंसी लाल की संपत्ति भुन्नू मल और लाला के पास चली गई। सुमेर सीजेजेंड. उन्होंने 15 दिसंबर, 1932 को अपने अधिकार आसा राम और तारा चंद को हस्तांतरित कर दिए और याचिकाकर्ता आसा राम के उत्तराधिकारी हैं। याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की बिक्री की

(1) आई.एल.आर. 1920 लाहौर 117.

वर्ष 1973 में और नौ स्टालों का निर्माण किया जो किरायेदारों को पट्टे पर दिए गए थे। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि राष्ट्रपति न्यायाधिकरण ने उन्हें फ़ार के नाम से लोकप्रिय आंगन के लिए मुआवजे की अनुमति न देकर गलती की।

(4) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने जवाब में, हालांकि मैंने याचिका में कही गई बातों का खंडन नहीं किया, लेकिन रिट याचिका के पैरा 12(6) में लगाए गए भौतिक आरोपों का खंडन नहीं किया। पैरा 12 का उप-पैरा (6) इस प्रकार है: -

“(vi) सौभाग्य से याचिकाकर्ताओं के लिए अधिग्रहण के तहत क्षेत्र से संबंधित सीधा निर्णय है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस पूरी मंडी को सरकार ने 1854 में मालिकों के दो समूहों को बेच दिया था और इस तरह इन्हें नवाब गंज और पाली गंज नाम दिया गया था। जहां तक नवाब गंज के मामले का सवाल है, इसका मुकदमा प्रिवी काउंसिल तक गया और एक फैसले में नवाब बहादुर मोहम्मद रुस्तम अल्ट खारी और अन्य बनाम करनाल की नगर समिति, आई.एल.आर. के रूप में रिपोर्ट की गई। 1920- खंड. मैं, पृष्ठ 117, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक आंगन को न तो सूखाया गया था, न ही हल्का किया गया था। नगरपालिका समिति द्वारा साफ की गई और संपत्ति के मूल्यांकन के रूप में इसकी प्रकृति से, नगरपालिका अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक सड़क नहीं होगी। निर्णयों सहित ऊपर उल्लिखित सभी प्रस्तुतियों को प्रस्तुतियों के समय सेवा में लाया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय पूरी तरह से गलत हो गया।

इस पैरा के संगत उत्तर में, यह इस प्रकार कहा गया था:

“इस उप-पैरा के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने फिर से उस मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश की है जो विचार के लिए मामले में उठता है। 1920 के निर्णयों का संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनावश्यक है क्योंकि 1920 के बाद बहुत पानी बह चुका है। देश के विभाजन के बाद, नगर पालिका, करनाल सड़कों का प्रबंधन कर रही थी और नालियां, स्ट्रीट लाइट आदि प्रदान कर रही थी। इसलिए, याचिकाकर्ता उक्त फैसले से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा पहले ही अक्षरशः पूरा हो चुका है

और आत्मा और इस प्रकार, वे ऊपर वर्णित किसी भी मुआवजे का दावा करने से वंचित हैं।

ट्रस्ट ने प्रांतीय सरकार से वर्ष 1854 में मालिकों के दो समूहों द्वारा की गई खरीद के संबंध में दावे से इनकार नहीं किया और दुकानों के सामने आंगन के संबंध में एक विवाद था, जिसे नगरपालिका समिति ने सार्वजनिक सड़क के रूप में दावा किया था। लेकिन मालिकों द्वारा टी के रूप में एक योजना (योजना संख्या 37), या 1215 वर्ग मापने वाला क्षेत्र। गज, मेरे संकल्प के अनुसार, धारा 3ओ या तुंजाब एक्सओन इम्प्रूवमेंट एक्ट (या संक्षेप में अधिनियम) के तहत नामांकन, बीपीएसमोअर 7, 197ओ को जारी किया गया था, और 1 जनवरी 197बी को अधिनियम की धारा 42 के तहत घोषणा जारी की गई थी। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि शुरू में प्रांतीय सरकार के स्वामित्व में थी और वर्ष 1804 में एक हॉल सर्वश्री हैती मल बंसी लाल को और दूसरा हॉल नवाब कुतुब दीन और गनुलम भानी खान को बेच दिया गया था। क्रमशः रेली गंज और नवाब गंज के रूप में संबंधित क्षेत्र। इसमें आयताकार आकार के दरवाजे थे, बाड़ों में दुकानें थीं और। रोनी पुरानी दुकानों में, आंगन होते थे जिनका उपयोग मुख्य रूप से किरायेदारों द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपने अनाज, सब्जियों को अलग-अलग ढेर में ढेर करने के लिए किया जाता था। दूसरी ओर दुकानों के प्रांगण मालिकों की निजी संपत्ति थे। 1920 में, नगरपालिका समिति, कमल, (या संक्षेप में समिति) ने बाड़े से होकर गुजरने वाली एक पक्की सड़क का निर्माण किया। समिति ने उस भूमि पर स्वामित्व का दावा किया जिस पर पक्की सड़क का निर्माण किया गया था और इसके कारण समिति और मालिकों के बीच नागरिक मुकदमेबाजी शुरू हो गई। जिला न्यायाधीश, करनाल ने कहा कि दुकानों के आयरनट का क्षेत्र मालिकों की निजी संपत्ति थी और समिति इस पर दावा नहीं कर सकती थी। लाहौर के मुख्य न्यायालय में अपील करने पर, जिला न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया गया, और इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि दुकानों के सामने का क्षेत्र समिति की संपत्ति थी। मालिकों ने आई.आहोर के मुख्य न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की और प्रिवी काउंसिल ने नवाब बहादुर मुहम्मद रुस्तम अल्ट खान और एक अन्य बनाम कदनाल की नगरपालिका समिति (1) में अपने फैसले में कहा कि जिस ज़मीन पर पक्की सड़क का निर्माण किया गया था वह मालिकों की निजी संपत्ति थी। इसने पुष्टि की कि दुकानों के सामने का क्षेत्र मालिकों की संपत्ति थी। मुख्य न्यायालय का निर्णय पलट दिया गया और जिला न्यायाधीश का निर्णय बहाल कर दिया गया।

(4) विजय कुमार और सुरिंदर कुमार याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पल्ली मल और बंसी लाल की संपत्ति भुन्नू मल और लाला के पास चली गई। सुमेर सीजेजेंड. उन्होंने 15 दिसंबर, 1932 को अपने अधिकार आसा राम और तारा चंद को हस्तांतरित कर दिए और याचिकाकर्ता आसा राम के उत्तराधिकारी हैं। याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की बिक्री की

(1) आई.एल.आर. 1920 लाहौर 117.

वर्ष 1973 में और नौ स्टालों का निर्माण किया जो किरायेदारों को पट्टे पर दिए गए थे। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि राष्ट्रपति न्यायाधिकरण ने उन्हें फ़ार के नाम से लोकप्रिय आंगन के लिए मुआवजे की अनुमति न देकर गलती की।

(4) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने जवाब में, हालांकि मैंने याचिका में कही गई बातों का खंडन नहीं किया, लेकिन रिट याचिका के पैरा 12(6) में लगाए गए भौतिक आरोपों का खंडन नहीं किया। पैरा 12 का उप-पैरा (6) इस प्रकार है: -

“(vi) सौभाग्य से याचिकाकर्ताओं के लिए अधिग्रहण के तहत क्षेत्र से संबंधित सीधा निर्णय है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस पूरी मंडी को सरकार ने 1854 में मालिकों के दो समूहों को बेच दिया था और इस तरह इन्हें नवाब गंज और पाली गंज नाम दिया गया था। जहां तक नवाब गंज के मामले का सवाल है, इसका मुकदमा प्रिवी काउंसिल तक गया और एक फैसले में नवाब बहादुर मोहम्मद रुश्तम अल्ट खारी और अन्य बनाम करनाल की नगर समिति, आई.एल.आर. के रूप में रिपोर्ट की गई। 1920- खंड. मैं, पृष्ठ 117, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक आंगन को न तो सूखाया गया था, न ही हल्का किया गया था। नगरपालिका समिति द्वारा साफ की गई और संपत्ति के मूल्यांकन के रूप में इसकी प्रकृति से, नगरपालिका अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक सड़क नहीं होगी। निर्णयों सहित ऊपर उल्लिखित सभी प्रस्तुतियों को प्रस्तुतियों के समय सेवा में लाया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय पूरी तरह से गलत हो गया।

इस पैरा के संगत उत्तर में, यह इस प्रकार कहा गया था:

“इस उप-पैरा के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने फिर से उस मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश की है जो विचार के लिए मामले में उठता है। 1920 के निर्णयों का संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनावश्यक है क्योंकि 1920 के बाद बहुत पानी बह चुका है। देश के विभाजन के बाद, नगर पालिका, करनाल सड़कों का प्रबंधन कर रही थी और नालियां, स्ट्रीट लाइट आदि प्रदान कर रही थी। इसलिए, याचिकाकर्ता उक्त फैसले से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा पहले ही अक्षरशः पूरा हो चुका है

और आत्मा और इस प्रकार, वे ऊपर वर्णित किसी भी मुआवजे का दावा करने से वंचित हैं।

ट्रस्ट ने प्रांतीय सरकार से वर्ष 1854 में मालिकों के दो समूहों द्वारा की गई खरीद के संबंध में दावे से इनकार नहीं किया और दुकानों के सामने आंगन के संबंध में एक विवाद था, जिसे नगरपालिका समिति ने सार्वजनिक सड़क के रूप में दावा किया था। लेकिन मालिकों द्वारा टी के रूप में नगरपालिका समिति में निहित थे और मालिक इन चरणों के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं थे। विद्वान न्यायाधिकरण ने उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय पक्षों की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। इस रिट याचिका में अधिग्रहीत भूमि का पिछला इतिहास दिया गया था। अन्य रिट याचिकाओं में, अधिग्रहीत भूमि का इतिहास विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट ने विवाद नहीं किया है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है; संपत्ति के मूल मालिक कौन थे, अधिग्रहण की विषय-वस्तु। पिछले मुकदमे में, वह संपत्ति जिसे अब फ़र्ज़ के नाम से जाना जाता है, मालिकों की संपत्ति मानी गई थी। प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। फिर भी, उस फैसले में मालिकों द्वारा इस अधिकार पर जोर दिया गया था कि दुकानों के सामने का प्रांगण उनकी संपत्ति है और नगरपालिका समिति ने यह दावा करते हुए इसका उल्लंघन किया कि प्रांगण इसमें निहित है क्योंकि इसका उपयोग एक मार्ग और समर्पण के रूप में किया जाता था। उपयोग. समिति की दलील खारिज कर दी गई और यह माना गया कि यह मालिकों की निजी संपत्ति थी। पिछले मुकदमे में निर्णय, हालांकि अंतर पक्ष नहीं, किसी लेनदेन या विशेष उदाहरण के सबूत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के तहत स्वीकार्य है, जिसमें प्रश्न में अधिकार का दावा किया गया था और मान्यता दी गई थी। श्रीनिवास कृष्णराव कांगो बनाम नारायण देवजी कांगो और अन्य (4) देखें।

(1) (1955) 1. एस.सी.आर. में।

(12) इस अदालत में मृतक-दावेदार इरा चंद के कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में धारा 42 या अधिनियम के तहत इस योजना और घोषणा को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस रिट याचिका में, (अनुलग्नक आर-2 की प्रतिलिपि, 1973 के सुधार मामले संख्या 136 में; पैरा 3 में यह इस प्रकार कहा गया था: -

“उक्त श्री तारा चंद की मृत्यु 12 अगस्त, 1970 को हुई और उनकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। 1 श्रीमती कैया वती, एक वसीयत के आधार पर संपत्ति में सफल रहीं और बाद में इन दुकानों के सामने एक खुली जगह सहित इस संपत्ति को वर्ष 1971 में एक पारिवारिक समझौते के आधार पर सभी याचिकाकर्ताओं को वितरित कर दिया गया।

लिखित बयान, एक्ज़िबिट आर-3 के संबंधित पैराग्राफ में, ट्रस्ट द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि दुकानों के सामने की खुली जगह मृतक तारा चंद की नहीं है। ट्रस्ट के वकील के एक बयान पर 13

मई, 1976 के एक आदेश, एक्ज़िबिट आर-एल द्वारा इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया गया था, जो इस प्रकार है: -

“प्रतिवादी नंबर 2, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विद्वान वकील श्री पी.एस. जैन ने हमारे सामने कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ता के दावे को इस हद तक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि विवाद में जमीन के मालिक तारा चंद मृतक जीवित थे। पांच उत्तराधिकारियों द्वारा, अर्थात्, श्रीमती। कला वती (विधवा), राम पार्षद और भागवत सरूप (बेटे, श्रीमती चंद्र किरण बंसल और श्रीमती सरला देवी (बेटियाँ)। विद्वान वकील ने माना कि नियमों के तहत ये पांच उत्तराधिकारी दुकान के लिए एक-एक प्लॉट के हकदार होंगे। और आगे यह कि मृतक तारा चंद के उत्तराधिकारी मृतक की पूरी भूमि, जो कि अधिग्रहित की जा रही है, के मुआवजे के हकदार होंगे, कानून के अनुसार। इस वचन दिए जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यह रिट याचिका को निरर्थक मानकर खारिज किया जा सकता है। हम तदनुसार आदेश देते हैं लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।”

ट्रस्ट ने उस मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के साथ यह मुद्दा नहीं उठाया कि दुकानों के सामने की संपत्ति का स्वामित्व मृतक तारा चंद के पास नहीं था। इसके विपरीत, ट्रस्ट के वकील द्वारा दिए गए बयान में) यह विशेष रूप से स्वीकार किया गया कि तारा के उत्तराधिकारी मृतक चांद पूरी जमीन के मुआवजे का हकदार होगा, जिसमें मृतक की दुकानों की आयरन की जमीन भी शामिल है। अकेले तारा चंद के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका में ट्रस्ट द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई थी कि दुकानों के सामने की संपत्ति मृतक के स्वामित्व में थी, लेकिन अन्य मामलों में एक अलग मानदंड अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसमें यह माना गया कि दुकान के सामने की जगह मालिकों की संपत्ति थी।

(12) ट्रिब्यूनल ने "सड़क" शब्द की परिभाषा का उल्लेख करने के बाद यह माना कि दावेदार दुकानों के सामने पड़े फड़ों के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसने रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों पर विचार नहीं किया, जिनका संबंधित प्रश्न के निर्धारण पर गहरा असर था। पक्षों की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया। तथ्य के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए दलीलों में की गई स्वीकारोक्ति पर विचार किया जाना चाहिए था। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय ट्रिब्यूनल ने भौतिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया। कहा जा सकता है कि उक्त निष्कर्ष रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कानूनी त्रुटि के कारण दूषित हुआ है। ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड पर लाए गए भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा और अपने फैसले में उसे नजरअंदाज नहीं किया, त्रुटि को सुधारना होगा।

(13) भले ही दुकानों के सामने की खुली जगह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम में परिभाषित सड़क हो, ट्रस्ट अधिनियम की धारा 45 के अनुरूप योजना को क्रियान्वित करने के लिए उस भूमि या सड़क को ले

सकता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अधिनियम की धारा 45 के तहत ट्रस्ट द्वारा कभी कोई कार्रवाई शुरू की गई थी।

(14) अधिनियम की धारा 46 उन सड़कों से संबंधित है जो अधिनियम की धारा 45 के तहत नगरपालिका समिति में निहित नहीं हैं और यह ट्रस्ट को सड़क के मालिकों को नोटिस जारी करने और उनकी सुनवाई के बाद कार्यभार संभालने का आदेश पारित करने का आदेश देती है। ऐसी सड़क या उसके भाग का, जिस भूमि का उनसे विनिवेश किया गया है, उसके मालिकों को मुआवजा देना होगा। इसे दुर्गा दास विनायक बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) में तय किया गया था, जहां इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

“अधिनियम की धारा 46 के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि यदि किसी निजी सड़क पर कब्जा करना है तो ट्रस्ट को विशिष्ट कार्रवाई करनी होगी। मैं

(1) 1979 पीएलजे 270।

वर्तमान मामले में, यह संदिग्ध है कि सड़क एक निजी सड़क है। जब अधिसूचना जारी की गई थी तब सभी भूमि एक खाली भूमि थी और धारा 36 के तहत अधिसूचना की अवधि और अधिनियम की धारा के तहत घोषणा के बीच ही याचिकाकर्ता ने भूखंड बेचकर अपनी खाली भूमि के एक हिस्से का निपटान किया और भूमि को छोड़ दिया। सड़क के उस उद्देश्य के लिए विवाद, जिस पर ट्रस्ट ने वास्तव में सड़क का निर्माण किया। योजना के आधार पर, सड़क, वास्तव में, एक निजी सड़क नहीं होगी - वह सड़क याचिकाकर्ता की भूमि पर ट्रस्ट द्वारा निर्मित एक सार्वजनिक सड़क होगी। मामले की परिस्थितियों में, भले ही भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को ट्रस्ट को उसकी शक्तियों के बारे में सलाह देने का अधिकार दे दिया जाए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रस्ट अधिनियम की धारा 46 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ता को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता है। ”

इस प्रकार, किसी भी कोण से देखने पर, फंडों को नगरपालिका समिति या ट्रस्ट की संपत्ति नहीं माना जा सकता है।

(16) ट्रिब्यूनल ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि यह सार्वजनिक सड़क थी या निजी सड़क। इसने केवल हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 83 में दी गई परिभाषा का उल्लेख किया और माना कि दुकानों के सामने की जगह एक सड़क थी। भले ही यह एक निजी सड़क हो, सड़क के नीचे की जगह मालिकों की संपत्ति होगी और मालिक उस भूमि के लिए मुआवजे के हकदार होंगे। यदि ट्रस्ट किसी निजी सड़क पर कब्जा करना चाहता है, तो वह अधिनियम की धारा 46 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जैसा कि पहले देखा गया था कि समिति और मालिकों के बीच मुकदमेबाजी में यह पुष्टि की गई थी कि पक्की सड़क के नीचे की भूमि जिसे अब फ़ार के नाम से जाना जाता है, मालिकों की संपत्ति थी। प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रासंगिक है। मालिकों के साथ मुकदमेबाजी में ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि दुकानों के सामने की जगह मालिकों की

संपत्ति थी। प्रवेश विबंध के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि इन्हें वापस लेने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार, मेरा मानना है कि फ़र्ज़ मालिकों की संपत्ति है और दावेदार इसके लिए मुआवजे के हकदार हैं। दावेदार उसी दर पर मुआवजे के हकदार हैं जैसा कि अधिग्रहीत निर्मित क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था, अर्थात्, रु। 1,336 प्रति वर्ग गज।

(17) दावेदार 1984 के अधिनियम संख्या 68 के लाभ के हकदार हैं। यह पुरस्कार 21 जनवरी 1988 को ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था और संशोधित अधिनियम के लाभों से उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता है।

(18) दावेदारों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उनके ग्राहक नियमों के तहत भूखंडों के आवंटन के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष दिया है कि भूखंडों का आवंटन नियमों के तहत किया गया है और कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

(19) कुछ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री बाली ने एक अतिरिक्त दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करने और फिर उसे आवंटित भूखंडों के मूल्य की सीमा तक कम करने में गलती की थी। स्थानीय विस्थापित व्यक्ति. पाई का कहना है कि मुआवजा, अर्थात् भूमि का मूल्य और वैधानिक लाभ पहले ही निर्धारित किया जाना चाहिए था और इस प्रकार निर्धारित मूल्य में से, स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूखंडों की कीमत काट ली जानी चाहिए थी। मुझे डर है, समर्पण टिकाऊ नहीं है। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि निर्धारित मुआवजे में से दावेदारों को आवंटित विकसित भूखंडों की कुल कीमत काट ली जाएगी। मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए दिए गए निर्देश में कोई खामी नहीं दिखती।

(20) श्री सरीन के प्रति निष्पक्षता में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिस स्थानीय प्राधिकारी के कहने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, वह कलेक्टर द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने मैसर्स इंडो स्विस् टाइम लिमिटेड दुंढाहेड़ा बनाम उमराव और अन्य, (6), मैसर्स कुलभूषण कुमार एंड कंपनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7), और संतोष कुमार और पर भरोसा किया। अन्य बनाम सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य (8)। मैं इस रिट याचिका में किए गए निवेदन की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रस्ट द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले पर हमले के प्रमुख आधारों को मेरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

(21) ट्रिब्यूनल के फैसले को इस हद तक संशोधित किया गया है कि फारस भूमि जिसे भूस्वामियों की संपत्ति नहीं माना जाता था, उसे उनकी संपत्ति माना जाएगा और वे उसी दर पर मुआवजे के हकदार होंगे जिस दर पर मुआवजा दिया गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। मूल्य से बाहर

(1) 1981 पी.एल.आर. 335.

(2) 1983 पी.एल.आर. 768.

(3) ए.आई.आर. 1986 एस.सी.' 1164.

इसलिए ट्रस्ट को देय मूल्यांकन विकास शुल्क में कटौती की जाएगी। ट्रिब्यूनल इस आदेश की प्राप्ति के छह महीने के भीतर, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रत्येक दावेदार की भूमि के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

(22) ट्रस्ट द्वारा दायर 1988 की रिट याचिका संख्या 8084, 8149 और 8172 को खारिज कर दिया गया है और दावेदारों द्वारा दायर 1988 की रिट याचिका संख्या 3488 से 3492 और 1989 की 2862, 2883, 2865, 2866 और 4159 को अनुमति दी गई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

(23) पक्ष 6 अक्टूबर 1989 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होंगे।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

दीपांशु सरकार  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)